applied for withdrawals of initial deposit amount;

(b) the number of such applicants who have claimed refund from Lohia Machines Limited, Kanpur, till 31st October, 1985;

(c) how much of the dues have already been refunded;

(d) details of expected yearly production figures for the next five years and the allocation made available for sale, yearly at each selling centre (name of the dealers city1wise; and

(e) the reasons for not increasing the production of Scooters?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) 4,03,082.

(c) About Rs. 20 crores.

(d) Estimated production for the 5 years is:

1985	72,000
1986	1,00,000
1987	1,25,000
1988	1,25,000
1989	1,25,000

In addition, Vespa Car Co. Ltd. promoted jointly by Lohia Machines Ltd. and Piaggio & C.S.P.A. of Italy and licensed to manufacture 200,000 two-wheelers per annum, will also supply scooters against the bookings of Lohia Machines Ltd. The company afforts vehicles to dealers every quarter broadly in proportion to respective bookings.

(e) The Company is stepping up scooter production as per the scheduled programme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2735. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983–84 में देश के 92 तथा 1984–85 में 84 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा हुआ जो क्रमश: 1534.31 तथा 1305.18 करोड़ रुपये था ; और

(ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने इनको घाटे से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983–84 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 92 उद्यमों ने कुल मिलाकर 1534.37 करोड़ रुपये का निवल घाटा उठाया है । 1984–85 के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के 1984–85 के उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 84 उद्यमों ने कुल मिलाकर 1305.15 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है ।

(ख) प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में कोई यथा निर्दिष्ट समिति नहीं गठित की गई है । किन्तु डा० अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता मे "सरकारी उद्यमो के सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने के लिये समिति" गठित की गई थी तथा सरकार इस समिति की सिफारिशों की फिलहाल जांच कर रही है ।

2736. [*Transferred to the 19th December*, 1985.]

भारी उद्योगों से जुड़े आनुषंगिक उद्योग

2737. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जापान जैसी कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक बड़े उद्योग के साथ जुड़े आनुषंगिक उद्योगो का जाल होता है तथा वहां गांवों को भी इसकी परिधि में ले लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार अब भी देश का सबसे निर्धन राज्य है जबकि यहां सभी प्रकार के